

मनोरंजन कर अधिकारी, हैदराबाद

बनाम

मैसर्स गीता एंटरप्राइजेज

सिविल अपील संख्या 4798/2008

निर्णय: 04.08.2008

एके माथुर और आफताब आलम न्यायाधीश

आंध्रप्रदेश मनोरंजन कर अधिनियम, 1939 - धारा 5(6)- मनोरंजन कर - सिनेमा थियेटर्स में कर का भुगतान करने का विकल्प चुना। धारा 5- स्थानीय क्षेत्र के उन्नयन के मद्देनजर कर में बदलाव जहां वे स्थित थे - विकल्प की वैधता की अवधि की समाप्ति के बाद अंतर राशि के लिए उठाई गई मांग - मांगे केवल अमान्य नहीं थी क्योंकि वे की समाप्ति के बाद उठाई गई थी विकल्प की अवधि - यदि विकल्प की अवधि के दौरान भिन्नता की आवश्यकता वाली परिस्थितियों में कोई बदलाव होता है तो प्राधिकरण किसी भी समय भी समय कर में बदलाव कर सकता है. आन्ध्रप्रदेश मनोरंजन कर नियम, 1939 - आर 27 (13)

उत्तरदाताओं - सिनेमा थियेटर्स ने आंध्रप्रदेश ई मनोरंजन कर अधिनियम, 1939 की धारा 5 के तहत स्लैब के आधार पर मनोरंजन कर का भुगतान करने का विकल्प सुना था। विकल्प की अवधि के दौरान जिस स्थानीय क्षेत्र में वे स्थित थे उसे अपग्रेड किया गया था। अपग्रेडेशन को देखते हुए टैक्स की रकम भी अलग-अलग थी, निर्धारित प्राधिकारी ने अंतर कर की राशि की मांग उठाई। उत्तरदाताओं ने मांग को चुनौती देते

हुए तर्क दिया कि मांग खराब थी क्योंकि इसे विकल्प की अवधि समाप्त होने के बाद उठाया गया था। उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और कहा कि कर में बदलाव करने की शक्ति को विकल्प की अवधि तक सीमित किया जाना चाहिए। इसलिए वर्तमान अपील करता है।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए

माना गया 1.1 विवादित मांगे किसी भी अमान्यता से ग्रस्त नहीं थी क्योंकि वे विकल्प की अवधि समाप्त होने के बाद उठाई गई थी। (पैरा 12) (872 डी-ई)

1.2 उच्च न्यायालय के अनुसार दरों में कोई संशोधन आन्ध्रप्रदेश मनोरंजन कर अधिनियम, 1939 की धारा 5(6) के तहत केवल तभी मान्य होगा जब धारा 5 की उपधारा (6) में निर्धारित चार घटनाओं में से कोई भी धारा के तहत दी गई अनुमति की अवधि के दौरान हुई हो। धारा 5(1) और निर्धारित प्राधिकारी ने उस अवधि के भीतर कर की निश्चित राशि को भी अलग करने का आदेश पारित किया। जब कोई आन्ध्रप्रदेश मनोरंजन कर अधिनियम, 1939 के नियम 27(13) पर आता है तो उच्च न्यायालय द्वारा धारा 5(6) पर रखा गया बी अर्थ कुछ समस्या को जन्म देता है। नियम 27(13) काफी स्पष्ट है और यह केवल का उपयोग करता है अभिव्यक्ति "किसी भी समय" न कि "ईस धारा के तहत अनुमत विकल्प की अवधि के दौरान" (पैरा 9 और 10) (871 ए-बी, 871 बी-सी) सी

1.3 उच्च न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 5(6) पर लगाया गया अर्थ स्वीकार्य नहीं है। अभिव्यक्ति "किसी भी समय इस धारा के तहत अनुमत विकल्प की अवधि के दौरान" निर्धारित प्राधिकारी की शक्ति को बिल्कुल भी संदर्भित नहीं करती, बल्कि यह उपधारा में गिनाई गई घटनाओं के घटित होने को संदर्भित करती है जो आधार बनेगी। कर की निश्चित राशि को अलग-अलग करें। वैकल्पिक रूप से लंबी

अभिव्यक्ति "किसी भी समय इस धारा के तहत अनुमत विकल्प की अवधि के दौरान" को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है पहला भाग, "इस धारा के तहत अनुमत विकल्प की अवधि के दौरान" होने वाली चार घटनाओं में से किसी एक को संदर्भित करता है और दूसरा भाग "किसी भी समय" निर्धारित प्राधिकारी को संदर्भित करता है। इस प्रकार पढ़े धारा 5 का अर्थ (6) स्पष्ट और स्पष्ट हो जाता है और नियम 27(13) को उसका सामान्य अर्थ वापस मिल जाता है इसे कोई जबरन प्रतिबंधित अर्थ देने की कोई आवश्यकता नहीं है। (पेरा 11) (871 एफ जी एच 872 बी-सी)

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता जून चैधरी व अनूप जी.चैधर, मनोज सक्सैना रजनीश कुमार सिंह, राहुल शुक्ला व टी.वी.जार्ज।

प्रत्यर्थी की ओर भास्कर रेड्डी एस.उदयकुमार सागर, बिना माधवन, वेनायगम (मैसर्स लायर्स नीट एण्ड कम्पनी के लिए) वी.श्रीधर रेड्डी एण्ड वी.एन. रघुपति।

आफताब आलम न्यायाधीश

1. पक्षों की बहस सुनी।

2. अनुमति दी गई।

3. सभी तीन अपीलें समान या समान तथ्यों से उत्पन्न होती हैं और इनमें कानून का एक सामान्य प्रश्न शामिल होता है। इसलिए तीनों अपीलों पर एक साथ सुनवाई की गई और इस फैसले द्वारा उनका निपटारा किया जा रहा है। विवाद आंध्र प्रदेश मनोरंजन कर अधिनियम, 1939 की धारा 5(6) के संदर्भ में निर्धारित प्राधिकारी द्वारा उठाई गई मांगों से संबंधित है क्योंकि प्रावधान भौतिक समय पर अस्तित्व में था (4.6.2005 से धारा 5 अब 2005 के अधिनियम 32 द्वारा हटा दी गई है)। विहित प्राधिकारी ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विवादित मांगें उठाई कि स्थानीय अधिकारियों जिनके अंतर्गत प्रतिवादियों के सिनेमा थिएटर स्थित थे को उस अवधि के

दौरान अपग्रेड किया गया था जब तीन उत्तरदाताओं को धारा 5 के तहत प्रदान की गई स्लैब प्रणाली के अनुसार अपने करों का भुगतान करने की अनुमति थी। अधिनियम। हालांकि मांगों जिस अवधि के लिए अनुमति दी गई थी वह समाप्त होने के काफी समय बाद उठायी गयी। मांगों की कानूनी वैधता के संबंध में विवाद धारा 5 की उपधारा (6) में होने वाली अभिव्यक्ति "किसी भी समय इस धारा के तहत अनुमत विकल्प की अवधि के दौरान" और अभिव्यक्ति "किसी भी समय" की व्याख्या पर आधारित है। "आंध्र प्रदेश मनोरंजन कर नियम, 1939 के नियम 27 के उप-नियम (13) में उपयोग किया जाता है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने उपरोक्त अभिव्यक्तियों की एक निश्चित तरीके से व्याख्या की है और यदि वह व्याख्या सही है तो उच्च न्यायालय ने जो निष्कर्ष निकाला है यह कि मांगें अमान्य और अप्रवर्तनीय थीं पूरी तरह से अस्वीकार्य है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उच्च न्यायालय की उन अभिव्यक्तियों की व्याख्या सही और ठोस है।

4. यहां, हम उन बुनियादी तथ्यों की चर्चा कर सकते हैं जो बहुत संक्षिप्त और निर्विवाद हैं। तीनों उत्तरदाता आंध्र प्रदेश सिनेमैटोग्राफिक अधिनियम और आंध्र प्रदेश मनोरंजन कर अधिनियम, 1939 के तहत अपेक्षित लाइसेंस लेकर फिल्मों के प्रदर्शन के व्यवसाय में लगे हुए हैं। मैसर्स के सिनेमा थिएटर गीता इंटरप्राइजेज एवं मैण् श्रीदेवी 70 एमएम (क्रमशः एसएलपी (सी) नंबर 9512/06 और एसएलपी (सी) नंबर 11420/06 में उत्तरदाता) चंदन नगर, सेरिलिंगमपल्ली में स्थित हैं। वित्तीय वर्ष 2001-02 और 2002-03 के लिए दोनों उत्तरदाताओं ने फॉर्म 3 में आवेदन करके और फॉर्म में अपने संबंधित परमिट फॉर्म 4 प्राप्त करके अधिनियम की धारा 5 (जैसा कि उस समय अस्तित्व में था) के अनुसार स्लैब के आधार पर मनोरंजन कर का भुगतान किया। सेरिलिंगमपल्ली जहां दो थिएटर स्थित हैं यह एक ग्रेड 3 नगर पालिका हुआ करती थी लेकिन 19.5.2001 को जारी एक सरकारी अधिसूचना द्वारा इसे 18.5.2000

से चयन ग्रेड नगर पालिका के रूप में अपग्रेड किया गया था यानी इस अवधि के दौरान दोनों उत्तरदाताओं को अपने करों का भुगतान करने की अनुमति दी गई थी। स्लैब सिस्टम के आधार पर यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि तालिका के संदर्भ में जो धारा 5 का हिस्सा थी चयन ग्रेड नगर पालिका में स्थित सिनेमा थिएटर ग्रेड 3 नगर पालिका में स्थित सिनेमाघरों की तुलना में कर की उच्च दर को आकर्षित करते थे। स्थानीय प्राधिकरण के उन्नयन के बावजूद, जिसके भीतर दो सिनेमा थिएटर स्थित थे अपीलकर्ता ग्रेड 3 नगर पालिका से संबंधित दर पर, अपने संबंधित परमिट में दिखाए गए अनुसार कर राशि का साप्ताहिक भुगतान करते रहे। निर्धारित प्राधिकारी ने दिनांक 31.08.2004 को गीता एंटरप्राइसेस से 10,19,875/- रुपये के अंतर कर की मांग की और मैसर्स श्रीदेवी के मामले 11,85,863/- रु. दिनांक 18.05.2001 से 31.03.2002 की अवधि की मांग की। निर्धारित प्राधिकारी ने दिनांक 01.06.2005 को एक और नोटिस जारी कर मेसर्स गीता एंटरप्राइजेज के खिलाफ 3,91,377/- रुपये की मांग अवधि 04.04.2002 से 27.06.2002 के लिये की गई। श्री देवी 70 एमएम ने आदेश दिनांक 30.5.2005 द्वारा वर्ष 2002-2003 के लिए संशोधित फॉर्म 4 के आधार पर 95820 रुपये की समान मांग की गई। एसएलपी (सी) संख्या 21778/2006 में प्रतिवादी कुमारी टॉकीज को निर्धारित प्राधिकारी द्वारा कर की अंतर राशि की समान मांग इस आधार पर दी गई थी कि विकल्प की अवधि के दौरान कृष्णा जिले में कैकलूर ग्राम पंचायत की आबादी जहां उत्तरदाताओं के सिनेमा थियेटर स्थित थे , बढ़ चुकी थी और 15000 से ज्यादा हो चुकी थी।

5. तीनों उत्तरदाताओं ने निर्धारित प्राधिकारी द्वारा उनके खिलाफ उठाई गई मांगों को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने तीन उत्तरदाताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और एम/एस स्वामी थियेटर सनथनगर बनाम उप वाणिज्यिक कर अधिकारी, संतनगर: WP Nos.8432/88

और 14970/89 में अपने पहले के निर्णय दिनांक 25.06.1992 पर भरोसा करते हुए विवादित मांगों को रद्द कर दिया।

6. यहां, स्वामी थिएटर (सुप्रा) के मामले में उच्च न्यायालय के फैसले पर जाने से पहले प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों पर एक नज़र डालना उपयोगी होगा। अधिनियम की धारा 5 ने थिएटर के मालिक को स्लैब के आधार पर मनोरंजन कर का भुगतान करने का विकल्प दिया। प्रावधान में कर के रूप में एक निश्चित साप्ताहिक राशि के भुगतान की अनुमति दी गई है, जो ऐसे कारकों के आधार पर निर्धारित किया जाता है जैसे कि स्थानीय प्राधिकारी की स्थिति जिसके भीतर सिनेमा थिएटर स्थित था और एयर कंडीशनिंग या एयर कूलिंग की सुविधाएं यदि कोई हो, प्रदान की गई थी। अनुभाग की उप-धारा(6) ने निर्धारित प्राधिकारी को उप-धारा में गिनाए गए चार घटनाओं में से किसी पर होने वाले कर की निश्चित राशि को अलग करने का अधिकार दिया। धारा 5(6), जब यह कानून की किताब में थी इस प्रकार थी:

(6). इस धारा के तहत अनुमत विकल्प की अवधि के दौरान उप-धारा (1) के तहत मालिक द्वारा देय कर की राशि को किसी भी समय अलग-अलग करना निर्धारित प्राधिकारी के लिए वैध होगा -

(ए) जहां उप-धारा (1) के तहत देय कर की राशि कानून द्वारा संशोधित की गई है; या

(बी) यदि मनोरंजन के स्थान के संबंध में वहां प्रवेश के लिए भुगतान की दर या बैठने की क्षमता या आवास में वृद्धि के कारण प्रति शो सकल संग्रह क्षमता में वृद्धि हुई है; या

(सी) जहां स्थानीय क्षेत्र जिसके संबंध में अनुमति दी गई है उन्नत किया गया है; या

(डी) यदि किसी कारण से यह पाया जाता है कि कर की राशि सही राशि से कम तय की गई है। (महत्व डालें)

7. इस संबंध में अन्य प्रासंगिक प्रावधान ए.ए.पी. मनोरंजन कर नियमों का नियम 27 था जो स्लैब के आधार पर मनोरंजन कर के भुगतान से संबंधित विवरण से संबंधित था। नियम 27 का उपनियम (13) इस प्रकार प्रदान किया गया है:

13. यदि मनोरंजन स्थल के संबंध में प्रति शो सकल संग्रह क्षमता में वृद्धि होती है तो मनोरंजन कर अधिकारी किसी भी समय अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत मालिक द्वारा देय कर की राशि को संशोधित कर सकता है अगर उसमें प्रवेश के लिए भुगतान की दरों या उसके बैठने की क्षमता या आवास के ऊपर के संशोधन के आधार पर या जहां स्थानीय क्षेत्र जिसके संबंध में अनुमति दी गई है को अपग्रेड किया गया है या यदि किसी कारण से यह पाया जाता है कि राशि कर सही राशि से कम तय किया गया है। (महत्व डालें)

8. अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के मद्देनजर उत्तरदाताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि निर्धारित प्राधिकारी के पास निस्संदेह धारा 5 के तहत निर्धारित कर की राशि को अलग करने की शक्ति है लेकिन शक्ति का प्रयोग केवल अवधि के दौरान ही किया जा सकता है जिसकी अनुमति दी गई थी। यह बताया गया कि तीन मामलों में विवादित मांगों स्वीकार्य रूप से अनुमति की अवधि समाप्त होने के काफी समय बाद उठाई गई थीं। इसलिए, विवादित मांगों खराब, अमान्य और अप्रवर्तनीय थीं। उच्च न्यायालय ने स्वामी थिएटर के पहले के फैसले पर भरोसा करते हुए, उत्तरदाताओं की दलीलों को बरकरार रखा विवादित मांगों को खारिज कर दिया और उत्तरदाताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं को अनुमति दे दी।

9. स्वामी थिएटर के मामले में एपी उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने

पहले माना था कि अभिव्यक्ति "किसी भी समय इस धारा के तहत अनुमत विकल्प की अवधि के दौरान" निर्धारित प्राधिकारी द्वारा शक्ति के प्रयोग पर एक सीमा लगाती है। अधिनियम की धारा 5(1) के तहत निर्धारित कर की राशि में भिन्नता है। डिवीजन बेंच ने इस प्रकार कहा:

"धारा 5 की उप-धारा (6) को पढ़ने से, जो निर्धारित प्राधिकारी को कर की राशि में बदलाव करने की शक्ति प्रदान करती है हमारी राय में स्पष्ट रूप से पता चलता है कि बदलाव करने की शक्ति विकल्प की अवधि तक ही सीमित होनी चाहिए। वह अवधि जिसके दौरान कर की राशि को बदलने की शक्ति "विकल्प की अवधि" है। प्रयुक्त भाषा विशिष्ट है और इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है। उप-धारा (6) में निर्धारित कर की राशि को अलग-अलग करने की शक्ति प्रदान करने वाले अधिकार क्षेत्र के तथ्य हैं:

- (1) प्रवेश के लिए भुगतान की दर में वृद्धि के कारण प्रति शो सकल संग्रह क्षमता में वृद्धि;
- (2) बैठने की क्षमता या आवास में वृद्धि;
- (3) उस स्थानीय क्षेत्र का उन्नयन जहां थिएटर स्थित है;
- (4) यदि किसी अन्य कारण से कर की कम दर तय की गई थी। यदि उपर्युक्त क्षेत्राधिकार तथ्य मौजूद हैं

धारा 6 के प्रारंभिक शब्द अर्थात् "किसी भी समय इस धारा के तहत अनुमत विकल्प की अवधि के दौरान उप-धारा (1) के तहत मालिक द्वारा देय कर की राशि को अलग करना निर्धारित प्राधिकारी के लिए वैध होगा" संचालन। शब्द "किसी भी समय" विकल्प की अवधि तक सीमित समय पहलू की सीमा को दर्शाते हैं। दूसरे शब्दों में विकल्प की अवधि "किसी भी समय" शब्दों से अनुमानित समय कारक को योग्य बनाती है।



इस प्रकार, उच्च न्यायालय के अनुसार, अभिव्यक्ति "किसी भी समय इस धारा के तहत अनुमत विकल्प की अवधि के दौरान" धारा 5(1) के तहत निर्धारित कर की राशि को अलग करने के लिए निर्धारित प्राधिकारी की शक्ति को संदर्भित करती है। इसलिए, धारा 5(6) के तहत दरों में कोई भी संशोधन केवल तभी मान्य होगा जब धारा 5 की उपधारा (6) में निर्धारित चार घटनाओं में से कोई भी धारा 5(1) के तहत दी गई अनुमति की अवधि के दौरान हुई हो। निर्धारित प्राधिकारी ने उस अवधि के भीतर कर की निश्चित राशि को भी अलग करने का आदेश पारित किया।

10. उच्च न्यायालय द्वारा धारा 5(6) पर रखे गए अर्थ ने नियम 27(13) पर आने पर कुछ समस्या का उद्गम हुआ। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, नियम 27 (13) काफी स्पष्ट है और यह केवल "किसी भी समय" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है न कि "इस धारा के तहत अनुमत विकल्प की अवधि के दौरान"। उच्च न्यायालय ने धारा 5(6) की व्याख्या के अधीन नियम को पढ़कर समस्या को दूर करने का प्रयास किया। उच्च न्यायालय ने कहा:

"सवाल यह है: क्या उप-नियम(13) में आने वाले शब्द "किसी भी समय" सीमा की अवधि की परवाह किए बिना कर को संशोधित करने के लिए प्राधिकरण को शक्ति प्रदान करते हैं? हमारा उत्तर नकारात्मक है। जब एक बार धारा विशेष रूप से केवल विकल्प की अवधि के दौरान कर में बदलाव करने की प्राधिकरण की शक्ति को कम कर देती है तो यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि कोई नियम प्राधिकरण को विकल्प की अवधि की परवाह किए बिना कर में बदलाव करने की शक्ति प्रदान कर सकता है। इसलिए, नियम 27 के उप-नियम (13) में आने वाले "किसी भी समय" शब्द की व्याख्या "विकल्प की अवधि के दौरान" कर को अलग करने की शक्ति को

सीमित करने के रूप में की जानी चाहिए। उप-धारा (6) में आने वाले शब्द "विकल्प की अवधि के दौरान" को उप-नियम (13) में पढ़ा जाना चाहिए। अन्यथा, यह अनुभाग अधिकारेतर होगा।"

11. हम अधिनियम की धारा 5(6) पर उच्च न्यायालय द्वारा अर्थ लगाई गई टिप्पणी से सहमत नहीं हो पा रहे हैं। हमारे विचार में, अभिव्यक्ति "किसी भी समय इस धारा के तहत अनुमत विकल्प की अवधि के दौरान" बिल्कुल भी निर्धारित प्राधिकारी की शक्ति को संदर्भित नहीं करती है बल्कि यह उपधारा में गिनाई गई घटनाओं के घटित होने को संदर्भित करती है जो कि कर की निश्चित राशि को अलग-अलग करने का आधार। अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम उप-धारा (6) क जहां तक कि वर्तमान के लिए प्रासंगिक, हैइस प्रकार पढ़ सकते हैं: जहां इस धारा के तहत अनुमत विकल्प की अवधि के दौरान किसी भी समय, स्थानीय क्षेत्र जिसके संबंध में यदि अनुमति प्रदान की जाती है तो उसे अपग्रेड कर दिया जाता है, निर्धारित प्राधिकारी के लिए उप-धारा के तहत मालिक द्वारा देय कर की राशि को अलग करना वैध होगा। वैकल्पिक रूप से लंबी अभिव्यक्ति "किसी भी समय इस धारा के तहत अनुमत विकल्प की अवधि के दौरान" को दो भागों में विभाजित किया जा सकता हैय पहला भाग, "इस धारा के तहत अनुमत विकल्प की अवधि के दौरान" होने वाली चार घटनाओं में से किसी एक को संदर्भित करता है और दूसरा भाग "किसी भी समय" निर्धारित प्राधिकारी को संदर्भित करता है। इस प्रकार पढ़ने पर धारा 5(6) का अर्थ स्पष्ट हो जाता है और नियम 27(13) को उसका सामान्य अर्थ वापस मिल जाता है उसे

कोई जबरन प्रतिबंधित अर्थ देने की आवश्यकता नहीं होती है।

12. ऊपर की गई चर्चाओं के मद्देनजर हम पाते हैं और मानते हैं कि स्वामी थिएटर के मामले में ए.पी. उच्च न्यायालय के फैसले ने सही कानून नहीं बनाया है। स्वामी थिएटर में निर्णय पर भरोसा करते हुए तीन उत्तरदाताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को तदनुसार रद्द कर दिया और यह माना जाता है कि विवादित मांगें किसी भी अमान्यता से ग्रस्त नहीं थीं, क्योंकि वे समय सीमा के बाद उठाई गई थीं। उच्च न्यायालय में उत्तरदाताओं द्वारा दायर सभी रिट याचिकाएं खारिज कर दी गईं। परिणामस्वरूप, अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

13. हालाँकि, यह स्पष्ट किया जा सकता है कि यह निर्णय पाता है और मानता है कि विवादित मांगें अमान्य नहीं थीं क्योंकि वे विकल्प की अवधि समाप्त होने के बाद उठाई गई थीं। यदि उत्तरदाताओं के पास विवादित मांगों के खिलाफ कोई अन्य शिकायत है तो वे अधिनियम के प्रावधानों के तहत, यदि कोई उपलब्ध हो समाधान तलाशने के लिए स्वतंत्र होंगे।

अपील स्वीकार

नोट- यह अनुवाद ऑटिफिशियल इन्टेलीजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सोनल ललवाणी (आर.जे.ऐसे.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।